क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 233, मंगलवार, 18 सितम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

ग्रेटर नोएडा में फॉर्चूनर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, दो की मौत

ग्रेटर नोएडा। एजेंसी। ग्रेटर नोएडा में सिरसा गोल चक्कर के पास रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ग्रेटर नोएडा थाने के प्रभारी (एसएचओ) धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि सिरसा गांव का रहने वाला जितेंद्र अपने रिश्तेदार संदीप और एक अन्य युवक के साथ फॉर्चूनर कार में फरीदाबाद से गांव लौट रहा था। उन्होंने बताया कि रविवार देर रात करीब ढाई बजे सिरसा गोल चक्कर के पास इनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जितेंद्र और संदीप ने दम तोड़ दिया। एसएचओ धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मां-बेटी से गैंगरेप के आरोपी आशु महाराज को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को स्वयंभू ज्योतिषी आशु महाराज उर्फ आसिफ खान को एक अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आशु महाराज पर एक महिला और उसकी बेटी से गैंगरेप करने का आरोप है। इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते गुरुवार को आशु महाराज को शाहदरा इलाके से इलाके से हिरासत में लिया था।

आशु बाबा पहले भी एक महिला को बना चुका है शिकार

जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला ने आशु महाराज उर्फ आसिफ खान के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया था कि बाबा ने दिल्ली के अपने आश्रम में उसके साथ कई सालों तक रेप किया। महिला के मुताबिक, बाबा के बेटे और दोस्तों ने भी उसका और उसकी बेटी का यौन शोषण किया। आरोपों के मुताबिक, महिला की बीमार बेटी का इलाज करने के बहाने आरोपी आशु महाराज ने उन्हें अपने रोहिणी के आश्रम में ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया।

आयुष्मान भारत योजना का ट्रायल शुरू, चार परिवारों को मिले गोल्डन कार्ड

गाजियाबाद। गाजियाबाद में आयुष्मान भारत योजना का ट्रायल सोमवार को संजयनगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल में हुआ। पहले दिन ट्रायल के तौर पर इंदरगढ़ी के अलग-अलग परिवारों के चार सदस्यों को गोल्डन कार्ड दिया गया। गोल्डन कार्ड पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गोल्डन कार्ड पाने वाले लाभार्थियों में मान्या, अशोक कुमार, अनीता देवी और कृष्णा ने कहा कि इस कार्ड के मिलने से अब निजी अस्पतालों में भी हम गरीब लोग अपना इलाज करा सकेंगे। अभी तक इलाज के लिए निजी अस्पताल जाना सपने जैसा होता था।

जनपद के 60 हजार लाभार्थियों को चुना

आयुष्मान भारत योजना के तहत जनपद के करीब 60 हजार लाभार्थियों को चुना गया है। पूरे देश में इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर को होनी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसका ट्रायल चल रहा है। इसी ट्रायल कार्यक्रम की शुरुआत गाजियाबाद में जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने संयुक्त जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर बने आयुष्मान भारत योजना के केंद्र का फीता काटकर की। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद लोगों को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी मॉनीटिरिंग की जाएगी।

पांच लाख तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा

सीएमओ डॉ. एनके गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत चुने गए गरीब परिवारों में से ट्रायल के तौर पर इंदरगढ़ी के अलग-अलग परिवारों से चार सदस्यों को पांच लाख तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा का गोल्डन कार्ड दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर से जिले के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में एक-एक आयुष्मान मित्र मौजूद रहेंगे।

इस कार्ड के जरिये लाभार्थी पूरे देश में कहीं पर भी मुफ्त इलाज करा सकता है।

हाईकोर्ट ने डीयू को डूसू चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम सुरक्षित रखने के निर्देश दिए

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह छात्र संघ (डूसू) चुनाव में इस्तेमाल की गईं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को सुरक्षित रखे। कोर्ट ने यह निर्देश कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के तीन उम्मीदवारों की याचिका पर दिया। इन लोगों ने डूसू चुनाव के परिणाम को चुनौती दी है।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि ईवीएम के अतिरिक्त पेपर ट्रेल और अन्य दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, चुनाव आयोग और हालिया चुनाव में जीतने वाले एबीवीपी के तीन उम्मीदवारों से भी जवाब मांगा।

एनएसयूआई ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

एनएसयूआई के तीन उम्मीदवारों सनी छिल्कर, मीना और सौरभ यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इस आधार पर चुनाव नतीजों को चुनौती दी कि वोटिंग मशीनों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। याचिका में मांग की गई कि डूसू चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम को सुरक्षित रखा जाए ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वो गायब नहीं हों। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सात ईवीएम से डाटा गायब हैं। याचिका में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। साथ ही सवाल उठाया गया है कि निजी तौर पर खरीदी गई ईवीएम का इस्तेमाल 12 सितंबर को हुए डूसू चुनावों में कैसे किया गया।

निजी ईवीएम का मुद्दा गरमाया

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पिछले गुरुवार को कहा था कि डूसू चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम चुनाव आयोग ने नहीं दिए थे और संभवत: उसे निजी तौर पर खरीदा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के 13 सितंबर को घोषित परिणाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) को अध्यक्ष सहित चार में से कुल तीन सीटों पर जीत मिली। वहीं, कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई को सिर्फ एक सीट मिली।

क्यों गुरुग्राम में एक साथ 55 स्पा सेंटर किए गए सील?

गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में के पांच मॉल सहित दूसरी जगहों पर चल रहे स्पा सेंटर्स के खिलाफ नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 स्पा सेंटर्स को सील कर दिया। नगर निगम की ओर से व्यावसायिक लाइसेंस नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। शहर में व्यावसायिक लाइसेंस के बिना बड़ी संख्या में स्पा सेंटर, सिनेमा हॉल संचालित हो रहे हैं। निगम की ओर से इन्हें व्यावसायिक लाइसेंस लेने को लेकर नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद स्पा सेंटर संचालकों ने व्यावसायिक लाइसेंस नहीं लिए। इसके बाद सोमवार को जोन चार में सीलिंग की कार्रवाई की गई। ओमैक्स सिटी सेंटर, ओमेक्स गुड़गांव, ओमेक्स सेलिब्रेशन, रहेजा और आईएलडी मॉल में 55 स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई। इस दौरान जब निगम अधिकारियों ने स्पा संचालकों से ट्रेड लाइसेंस मांगे तो व्यावसायिक लाइसेंस नहीं दिखाए जाने पाने पर उन्हें सील कर दिया गया।

निगमायुक्त ने दिए थे निर्देश

नगर निगम क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के लिए व्यावसायिक लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। निगमायुक्त ने व्यावसायिक लाइसेंस की समीक्षा करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद संयुक्त निगमायुक्त 4 रविन्द्र यादव ने कराधान अधिकारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। इसके बाद हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 330, 331, 335 और 336 के तहत कार्रवाई की गई। नगर निगम क्षेत्र में व्यावसायिक प्रमाण पत्र के बिना व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित नहीं हो सकते। ऐसे में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सीलिंग की कार्रवाई आगे जारी रहेगी। -यशपाल यादव, निगमायुक्त (नगर निगम गुरुग्राम)

फाटक नहीं खोलने पर रेलवे गेटमैन के हाथ-पैर काट डाले

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में रेलवे के एक गेटमैन पर क्रॉसिंग गेट नहीं खोलने पर बुरी तरह से हमला किया गया। इस दौरान बेरहम बदमाशों ने पहले तो गेटमैन को बुरी तरह पीटा और फिर उसके हाथ और पैर काट दिए। गेटमैन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नरेला और रठधना के बीच रेलवे लेवल गेट नंबर 19 पर तैनात कुंदन पाठक पर तीन बाइक सवारों ने हमला कर दिया। पाठक ने 18101 मुरी एक्सप्रेस के आने की वजह से गेट खोलने से मना कर दिया था। इससे गुस्साए बदमाशों ने पाठक के दोनों हाथों और पैरों को काट दिया और इस दौरान उनके गले को भी चोट पहुंचाई। अधिकारी ने कहा कि पाठक को नई दिल्ली स्थित रेलवे सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी सर्जरी हो रही है। घटना की जानकारी मिलते ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी अस्पताल का दौरा किया और पाठक की स्थिति की जानकारी ली। अधिकारी ने कहा कि रेलवे इलाज का सारा खर्च उठा रही है ताकि वह जिंदा बच सकें और हमारे बीच दोबारा आ सकें। उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गेटमैन पर हुए हमले के बाद लगभग पांच ट्रेनों के परिचालन में देरी हुई। घटना रविवार देर रात 12 बजकर 40 मिनट पर हुई। बिहार के बांका जिले के रहने वाले पाठक 2013 में रेलवे में भर्ती हुए थे।

अब आपके घर का मलबा खरीदेगा गाजियाबाद नगर निगम

गाजियाबाद। शहर में मकानों की टूट-फूट से निकला पक्का मलबा भी अब आपकी कमाई कराएगा। आपके घर से निकले पक्के मलबे को नगर निगम खरीदेगा। इसके लिए रेट भी तय कर दिए गए हैं। अगले सप्ताह से योजना को लागू करने की तैयारी चल रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार इसकी थीम कूड़ा निस्तारण रखी गई है। निगम अपने क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े को पूरे तरह से निस्तारित करने की योजना बना रहा है। घरों से निकलने वाले कूड़े को लेकर डोर-टू डोर अभियान शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं हर जोन में दो-दो वेस्ट कंपोस्टर प्वाइंट भी बनाए जा रहे हैं, जहां पूरे जोन का कूड़ा डालकर उसके कंप्रेस्ड किया जाएगा। उसके बाद कूड़े को डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाएगा।

मलबे की खरीद के लिए रेट भी तय

मलबे को खरीदने के लिए निगम की ओर से रेट भी तय कर दिए गए हैं। इसके लिए मकान मालिक को निगम 260 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से पैसा देगा। निगम मलबे के लिए अलग से नंबर भी जारी करेगा। निगम की गाड़ी बताए गए पते पर पहुंचेगी और मलबे की नापकर उठाकर ले जाएगा।

सड़क निर्माण और भराव में होगा इस्तेमाल

नगर निगम पक्के मलबे को उठाकर इसका अपने कार्य में इस्तेमाल करेगा। निगम की भूमि को समतल करने के साथ कई ऐसे स्थान होंगे, जहां भराव करना है, ऐसे स्थानों को निगम चुनेगा।

रिलायंस के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा केंद्र

विधि मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने पर अपनी मंजूरी दी है।

नई दिल्ली ■ एजेंसी

ओएनजीसी-रिलायंस गैस चोरी मामले में सरकार रिलायंस के खिलाफ फिर अदालत जाने की तैयारी में है। विधि मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने पर अपनी मंजूरी दी है। ओएनजीसी के गैस क्षेत्र से रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा कथित तौर पर गैस निकाल लिए जाने के मामले में सरकार द्वारा रिलायंस से 1.50 अरब डॉलर की मांग को मध्यस्थता अदालत ने खारिज कर दिया था। इस समूचे घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। तेल मंत्रालय के इस संबंध में विधि मंत्रालय से सुझाव मंगाया था।

सूत्रों ने कहा कि विधि मंत्रालय के अनुसार, मध्यस्थता अदालत का बहुमत से दिया गया निर्णय उत्पादन भागीदारी अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है, इसमें आवश्यक कारणों की कमी है और यह सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है। तीन सदस्यीय मध्यस्थता अदालत ने जुलाई में बहुमत के साथ निर्णय दिया था। इसमें कहा गया कि रिलायंस उसके क्षेत्र से निकलने वाली कोई भी गैस का उत्पादन अथवा बिक्री कर सकता है। रिलायंस उस गैस को भी निकाल सकता है जो कि उसके साथ लगते दूसरे क्षेत्र से उसमें आ गई हो।

रिलायंस के क्षेत्र के साथ ही ओएनजीसी का तेल-गैस क्षेत्र है। इस गैस को निकालने के लिए उसे सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं है। विधि मंत्रालय का मानना है कि मध्यस्थता अदालत ने अनुबंध के दायित्वों को नजरअंदाज किया है। गैस के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की सूचना सरकार को देने की विधायी जिम्मेदारी का कंपनी द्वारा उल्लंघन किए जाने को नजरअंदाज किया। मंत्रालय मानता है कि इस मामले में फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

मोदी ने दोस्त अनिल अंबानी व गौतम अडाणी के फायदे के लिए किया रक्षा मंत्रालय के साथ खिलवाड़: कांग्रेस

राफेल सौदे को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने करीब 100 मध्यम बहुपयोगी लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदाएं जारी कीं। उन्होंने दावा किया कि अडाणी डिफेंस सिस्ट्म्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने विमान की आपूर्ति के लिए स्वीडिश रक्षा कंपनी साब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक एनजीओ द्वारा आयोजित की एक संगोष्ठी में कह कि (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी ने अपने दोस्तों अनिल अम्बानी और गौतम अडाणी को फायदा पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ''इज मोदी रियली गिल्टी इन राफेल डील?' (क्या मोदी सच में राफेल सौदे में दोषी हैं) विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कहा, ''राफेल सौदे के लिए रिलायंस डिफेंस के गठन के बाद अडाणी डिफेंस सिस्ट्म्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का गठन किया गया।

पाकिस्तान-चीन क्षेत्र में शांति के लिए प्रसासरत: मसूद

इस्लामाबाद ,(एजेंसी)। चीन में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खालिद ने कहा है कि दोनों देश क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए मिलकर काम रहे हैं। 'रेडियो पाकिस्तान'की रिपोर्ट के अनुसार'चीन-पाक आर्थिक गलियारा'की वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में नया आयाम जुड़ने के साथ ही इससे कम से कम 10 हजार पाकिस्तानी नागरिकों को नौकरियां मिली हैं। श्री खालिद ने शनिवार को पाकिस्तान टीवी के साथ बाताचीत के दौरान कहा कि चीन के नौ विश्वविद्यालयों में उर्दू पढ़ाई जा रही है और करीब 25 हजार पाकिस्तानी छात्र चीन के शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन में पाकिस्तानी फिल्मों और नाटकों का प्रचार - प्रसार की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही, दोनों देशों के मीडिया के बीच संपर्क को भी मजबूत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

चीन के नौ विवि में उर्दू पढ़ाई जा रही है

महिलाओं के खिलाफ अपराध विरोधी कानून का क्या हुआ: सुप्रिया सुले

मुंबई,(एजेंसी)। हरियाणा में सामूहिक दुष्कर्म की घटना की पृष्ठभूमि में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए बनाए गए कानून को क्या वाकई में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए।

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में तीन लोगों ने 19 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। सुले ने एक बयान में कहा कि एक महिला होने के नाते मैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले प्रधानमंत्री से न्याय की मांग करती हूं। लोकसभा में बारामती क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सुले ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे दिखे कि जो कुछ कहा जा रहा है, उसे लागू किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए

एनसीपी नेता ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कानून है, लेकिन क्या इन कानूनों को लागू किया गया है? मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और जवाब देना चाहिए। सुले ने सरकार के एक आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में लापता लड़कियों की संख्या करीब 3000 है ।

राजनीति

2019 में गठबंधन तभी होगा जब हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी

माया बोली-मेरा किसी से बुआ-भतीजे का रिश्ता नहीं

लखनऊ ■ एजेंसी

2019 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए यूपी में संभावित महागठबंधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन तभी होगा जब हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, नहीं तो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी।

हाल ही में जेल से रिहा हुए भीम आर्मी के मुखिया चन्द्रशेखर रावण की बुआ वाली टिप्पणी पर मायावती ने दो टूक कहा कि उनका किसी के साथ भाई-बहन या बुआ-भतीजे का रिश्ता नहीं है। बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद सहारनपुर दंगे के आरोपी रावण ने मायावती की खुलकर तारीफ की थी। मायावती को बुआ समान बताते हुए रावण ने अपने समर्थकों से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील की है। रावण की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर मायावती ने कहा, मेरा ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा रिश्ता सिर्फ आम आदमी, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े लोगों से है। बीएसपी सुप्रीमो ने दो टूक कहा कि उनका किसी के साथ भाई-बहन या बुआ-भतीजे का रिश्ता नहीं है।

...तो अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी: बीजेपी के खिलाफ यूपी में गठबंधन के बारे में मायावती ने कहा,हम किसी भी जगह और किसी भी चुनाव में गठबंधन के लिए तैयार हैं लेकिन यह तभी होगा जब हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं हुआ तो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस दौरान मायावती ने बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन को अहम भी बताया। माना जा रहा है कि मायावती ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीटों के बंटवारे से पहले दबाव बनाने की रणनीति के तहत यह बयान दिया है। दरअसल, यूपी में काफी समय से एसपी-बीएसपी और कांग्रेस के बीच बिहार की तर्ज पर 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की अटकलें लगती रही हैं। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर ये पार्टियां साफ तौर पर कुछ भी कहने से बचती रही हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव जरूर बीच-बीच में बीएसपी के साथ गठबंधन के संकेत देते रहे हैं।

महंगाई पर बीजेपी को घेरा

उधर, प्रेस वार्ता में मायावती ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा। मायावती ने कहा कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में विफल रही है। उन्होंने नोटबंदी का भी जिक्र किया और कहा कि नोटबंदी राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में सामने है। वहीं, राफेल घोटाले को लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो ने बीजेपी पर निशाना साधा।

छात्र संघ चुनाव नतीजों के बाद एबीवीपी और वाम कार्यकर्ता भिड़े

नई दिल्ली, एजेंसी। जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनाव के नतीजे घोषित होने के कुछ समय बाद सोमवार को आरएसएस से संबद्ध एबीवीपी और वाम समर्थित आईसा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वाम छात्र समूहों के संयुक्त मोर्चा ने रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उम्मीदवारों को बड़े अंतर से हराकर छात्रसंघ के सभी चार केन्द्रीय पैनल पदों पर जीत हासिल की। नवनिर्वाचित जेएनयूएसयू अध्यक्ष एन. साई बालाजी ने आरोप लगाया कि सोमवार सुबह एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई की। उन्होंने कहा कि एबीवीपी के सदस्यों ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) के कार्यकर्ताओं पर हमला किया और जब मैंने और कुछ अन्य ने दखल देने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर भी हमला किया।

वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज

बालाजी ने दावा किया कि एबीवीपी सदस्यों ने उन पर तब भी हमला किया जब पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) का वाहन उन्हें जेएनयू परिसर से बाहर ले जा रहा था। हालांकि, एबीवीपी ने दावा किया कि आईसा कार्यकर्ताओं ने उनके सदस्यों को पीटा। एबीवीपी और आईसा दोनों ने वसंत कुंज पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है।

जेएनयू में पुलिस फोर्स तैनात

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) देवेन्द्र आर्य ने बताया कि हालात अब नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि पीसीआर को तड़के करीब तीन बजे फोन पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच हाथापाई की सूचना मिली थी। इसके बाद हमने विश्वविद्यालय अधिकारियों, छात्रों एवं प्रोफेसरों के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने में शिकायतें मिली हैं।

दखल

किसानों की दशा सुधारने की सार्थक पहल

पिछले दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण नीति' को मंजूरी दी है। एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आयोग ने भी वर्ष 2006 में यही युक्ति सुझाई थी। समर्थन मूल्य में की गई इन वृद्धियों से ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कृषि भूमि का किराया भी इस मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। इन वृद्धियों से कृषि क्षेत्र की विकास दर में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

समय पर किसान द्वारा उपजाई फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाने के कारण अन्नदाता के सामने कई तरह के संकट मुंहबाए खड़े हो जाते हैं। ऐसे में वह न तो बैंकों से लिया कर्ज समय पर चुका पाते हैं और न ही अगली फसल के लिए वाजिब तैयारी कर पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई और शादी भी प्रभावित होते हैं। यदि अन्नदाता के परिवार में कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसका इलाज कराना भी मुश्किल होता है। इन वजहों से उबर नहीं पाने के कारण किसान आत्मघाती कदम उठाने तक को मजबूर हो जाते हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए ही राजग सरकार ने पिछले दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, जिससे किसान की आमदनी दोगुनी हो जाए और अब इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण नीति' को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए 15 हजार 53 करोड़ रुपए मंजूर किए है। अब यदि बाजार में फसल का मूल्य एमएसपी से कम होगा तो राज्य सरकारें इन योजनाओं में से किसी एक का चुनाव कर किसानों को धनराशि का भुगतान कर सकती हैं।

राजग सरकार ने चार साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद अब किसानों की गंभीरता से सुध लेना शुरू किया है। अन्नदाता आय संरक्षण नीति के तहत राज्य सरकारों को तीन प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। एक, नीति के तहत राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर फसलों की खरीद करनी होगी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत होगी। दूसरी भावांतर भुगतान योजना और तीसरी प्रायोगिक तौर पर निजी क्षेत्रों को भी एमएसपी पर खरीद में छूट दी गई है। इसके लिए इन्हें अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। निःसंदेह इन नीतियों से बाजार की संरचना किसान के हित में मजबूत होगी। साथ ही यदि फसल बीमा का समय पर भुगतान, आसान कृषि ऋण और बिजली की उपलब्धता तय कर दी जाती है तो किसान की आमदनी दूनी होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ऐसे ही उपायों से खेती की लागत कम करने और आय में वृद्धि के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ऐसा होता है तो किसान और किसानी से जुड़े मजदूरों का पलायन रुकेगा और खेती 70 फीसदी ग्रामीण आबादी के रोजगार का जरिया बनी रहेगी। खेती घाटे का सौदा न रहे इस दृष्टि से कृषि उपकरण, खाद, बीज और कीटनाशकों के मूल्य पर नियंत्रण भी जरूरी है। इन वस्तुओं के निर्माता किसानों को नकली खाद, बीज व कीटनाशक देकर भी बर्बाद करने में लगे हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। अब इसे पूरा करना इसलिए जरूरी हो गया था, क्योंकि कुछ माह में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और इसके ठीक चार माह बाद मई 2019 में आम चुनाव होने हैं। हालांकि कुछ खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से ही लागत मूल्य का डेढ़ गुना है। लेकिन धान, रागी और मूंग आदि का समर्थन मूल्य लागत की डेढ़ गुनी कीमत से कम है। इन फसलों के उत्पादक किसानों को इस मूल्य वृद्धि से सबसे अधिक लाभ होगा। एमएसपी में न्यूनतम 3.7 प्रतिशत और अधिकतम 52.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे सरकारी खजाने पर 33 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। इस नए मूल्य निधारण से धान की खरीद पर ही 15 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ की उम्मीद है। किसानों की आमदनी में यह बढ़ोतरी व्यापक रूप से देषहित में है। दरअसल किसान की आमदनी बढ़ने से चौतरफा लाभ होता है। फसलों के प्रसंस्करण से लेकर कृषि उपकरण और खाद-बीज के कारखानों की गतिशीलता किसान की आय पर ही निर्भर है। मंडियों में आढ़त, अनाज के भरा-भर्ती और यातायात से जुड़े व्यापरियों को भी जीवनदान किसान की उपज से ही मिलता है।

किसान, गरीब और वंचित तबकों की हैसियत बढ़ाने की दृष्टि से आवास और उज्ज्वला योजनाओं के बाद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण नीति सरकार की चौथी बड़ी पहल है। हालांकि इसके पहले पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए 8,500 करोड़ का पैकेज दिया है। फसल बीमा योजना और भूमि स्वास्थ्य कार्ड भी इसी कड़ी के हिस्सा रहे हैं। बीते चार आम बजटों में भी कई सिंचाई योजनाओं को मंजूर किया गया है, जिससे वर्षा पर निर्भरता कम हो। गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों को बीमार होने पर पांच लाख रुपए तक की आर्थिक मदद के अहम् प्रावधान किए हैं। मोदी सरकार के ये ऐसे काम हैं, जिन पर यदि उचित व ईमानदारी से क्रियान्वयन होता है तो किसान और गरीब मजदूर का कल्याण तो होगा ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी की वापसी हो सकती है। इन योजनाओं के वजूद में आ जाने से कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों द्वारा मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार साबित करने के प्रयास किए जा रहे थे, उनको भी पालीता लगना तय है। ये उपाय किए जाना इसलिए जरूरी थे, क्योंकि अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के बावजूद देश में कृषि उत्पादन चरम पर है। सरकार द्वारा पेश आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016-17 में करीब 275 मिलियन टन खाद्यान्न और करीब 300 मिलियन टन फलों व सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। बावजूद किसान सड़कों पर उपज फेंकते हुए आंदोलित थे व आत्महत्या भी कर रहे थे, लिहाजा किसी भी सरकार के लिए किसान चिंतनीय पहलू होना चाहिए था।

गोया, इसकी पृष्ठभूमि 2018-19 के आम बजट में ही रख दी गई थी। हालांकि कृषि, किसान और गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सरकार की कृपा नहीं बल्कि दायित्व है, क्योंकि देश की आबादी की आजीविका और कृषि आधारित उद्योग अंततः किसान द्वारा खून-पसीने से उगाई फसल से ही गतिमान रहते हैं। यदि ग्रामीण भारत पर फोकस नहीं किया गया होता तो जिस आर्थिक विकास दर को 8 प्रतिशत तक लाया जा सका है, वह संभव ही नहीं थी। इस समय पूरे देश में ग्रामों से मांग की कमी दर्ज की गई है। निःसंदेह गांव और कृषि क्षेत्र से जुड़ी जिन योजनाओं की श्रृंखला को जमीन पर उतारने के लिए 14.3 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, उसका उपयोग अब सार्थक रूप में होते लग रहा है। ऐसे ही उपायों से किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो पाएगी। इस हेतु फसलों का उत्पादन बढ़ाने, कृषि की लागत कम करने, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की भी जरूरत है। बीते कुछ सालों में कृषि निर्यात में सालाना 10 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कृषि आयात 10 अरब डॉलर से अधिक बढ़ गया है।

केंद्र सरकार फिलहाल एमएसपी तय करने के तरीके में 'ए-2' फॉर्मूला अपनाती रही है। यानी फसल उपजाने की लागत में केवल बीज, खाद, सिंचाई और परिवार के श्रम का मूल्य जोड़ा जाता है। इसके अनुसार जो लागत बैठती है, उसमें 50 फीसदी धनराशि जोड़कर समर्थन मूल्य तय कर दिया जाता है। जबकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है कि इस उत्पादन लागत में कृषि भूमि का किराया भी जोड़ा जाए। इसके बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि जोड़कर समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फसल का अंतरराष्ट्रीय भाव तय करने का मानक भी यही है। यदि भविष्य में ये मानक तय कर दिए जाते हैं तो किसान की खुशहाली और बढ़ जाएगी।

प्रमोद भार्गव
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

दवाओं पर बैन का फैसला सही

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए कहा है कि मरीजों के स्वास्थ्य से बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता; ये दवाएं मरीजों की सेहत को लेकर तय मानकों पर खरी साबित नहीं उतरती हैं।

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जो दवा सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, लोगों को किसी बीमारी की हालत में न केवल सेवन करना पड़ता है, बल्कि खुद डॉक्टर भी वे दवाएं लेने की सलाह देते हैं। सही है कि इन दवाओं के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी आम नहीं होती, इसलिए साधारण लोगों को पता नहीं चल पाता कि किस दवा को खाने से कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य पर उसके दूसरे असर भी हो सकते हैं। आमतौर पर प्रशिक्षित डॉक्टर भी ऐसी दवा लेने की सलाह दे देते हैं, जो मरीज की स्थिति में तात्कालिक सुधार तो करती हैं, लेकिन शरीर में किसी दूसरी परेशानी की वजह बन सकती हैं। दवा कंपनियों से लेकर डॉक्टरों तक की लापरवाही या मिलीभगत की वजह से यह धंधा निर्बाध गति से चल रहा है। इस लिहाज से देखें तो सरकार ने जिस तरह 328 दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की है, वह आम नागरिकों की सेहत का खयाल रखने के लिहाज से जरूरी कदम है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए कहा है कि मरीजों के स्वास्थ्य से बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता; ये दवाएं मरीजों की सेहत को लेकर तय मानकों पर खरी साबित नहीं उतरती हैं। अब सवाल है कि जिन दवाओं पर रोक लगाई गई है, बाजार में उन्हें बिक्री के लिए उतारने से पहले क्या उनके दुष्परिणामों के लिहाज से परीक्षण किया गया था? अब तक अगर ये दवाएं खुले बाजार में बिक रही थीं, डॉक्टर उन्हें लेने की सलाह दे रहे थे और मरीज उनका सेवन कर रहे थे तो उनका असर लोगों पर क्या हुआ होगा? यह एक अफसोसजनक स्थिति है कि अब तक इन दवाओं का उपयोग करने वाले मरीज अपनी बीमारी का इलाज कराते हुए अघोषित रूप से क्लिनिकल ट्रायल का जरिया बन गए।

अगर दवाओं के दुष्परिणामों के मद्देनजर किसी व्यक्ति की सेहत पर कोई दीर्घकालिक असर पड़ा होगा, तो उनसे होने वाले नुकसान की जवाबदेही किस पर होगी? ऐसी कई दवाइयां हैं, जो विदेशों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन हमारे यहां वे धड़ल्ले से बिकती रही हैं और उनके सेवन की सलाह बाकायदा प्रशिक्षित डॉक्टर भी देते रहे हैं। जाहिर है, इसके पीछे इस बात की निश्चिंतता काम करती होगी कि औषधि मानकीकरण से संबंधित महकमे के सख्त परीक्षण के दौर से गुजरने के बाद ही किसी दवा को बाजार में उतारा गया होगा। दूसरे, यह किसी से छिपा नहीं है कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को कैसे प्रभावित करने की कोशिश करती रही हैं। यही वजह है कि कई बार कुछ डॉक्टर किसी रोग के इलाज के लिए ऐसी दवाएं भी लेने की सलाह दे देते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। देश में स्वास्थ्य के मसले पर इलाज से लेकर दवाओं के इस्तेमाल के बारे में इस तरह की लापरवाही के मामले आम रहे हैं।

डूसू ने पेश की युवाओं की सोच

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के परिणाम हमेशा पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के मन की तस्वीर पेश करने का काम करते हैं, क्योंकि डूसू में देश के कोने-कोने से आए छात्र यहां तालीम लेते हैं। डूसू इलेक्शन को सीधे आम चुनाव से जोड़कर ही देखा जाता है। छात्र नेता के रूप में यहां से निकलने वाले ज्यादातर नेता उच्च सियासत में प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लिहाज से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव को बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं। हाल ही में संपन्न डूसू चुनाव के परिणाम ने यह दर्शा दिया है कि युवा अब भी भाजपा के पक्ष में हैं। भाजपा-आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चार में से तीन सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा।

हाल ही में संपन्न डूसू चुनाव के परिणाम ने यह दर्शा दिया है कि युवा अब भी भाजपा के पक्ष में हैं। भाजपा-आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चार में से तीन सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। यह परिणाम दूसरे दलों की परेशानी बढ़ाने वाला है।

एबीवीपी के प्रत्याशी अंकिव बसोया अध्यक्ष, शक्ति सिंह उपाध्यक्ष व ज्योति चौधरी ने संयुक्त सचिव पद पर जीत का परचम लहराया। एनएसयूआई के आकाश चौधरी ने सचिव पद पर जीत दर्ज की है। चुनाव नतीजों से एक संकेत मिला है। दरअसल इससे परोक्ष रूप से लोकसभा चुनाव पर असर जरूर पड़ेगा। छात्र राजनीति को चोटी की सियासत की पहली सीढ़ी माना जाता है। इस बात का उदाहरण भी हमारे पास मौजूद है। देश की सबसे बड़ी पाठशाला दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश को कई बड़े कई राजनेता दिए हैं। मौजूदा सरकार में कई मंत्री यहीं की देन हैं। इसलिए यहां होने वाले छात्रसंघ चुनाव पर सबकी नजरें होती हैं। डीयू के चुनाव कई मुद्दों को प्रभावित करते हैं। इन चुनावों से राजनीतिक पार्टियां युवाओं के मूड का आकलन करती हैं, जिसका असर बड़े चुनावों में देखने को मिलता है। क्योंकि हर बड़े चुनाव में युवाओं का रोल बड़ा माना जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में दोनों बड़ी पार्टियां भाजपा-कांग्रेस अपना दमखम दिखाने का काम करती हैं। उम्मीवारों को विजय बनाने के लिए पूरी ताकतें झोंकती हैं।

पार्टियां आम चुनावों की तरह पैसा बहाती हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, प्रचार-प्रसार होता है। कॉलेज परिसर के अलावा पूरी दिल्ली पोस्टरों से पटी दिखाई पड़ती है। बड़े नेता चुनाव प्रचार करने कालेज जाते हैं। छात्रों को लुभाने के लिए लोक लुभावने वायदे किए जाते हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से चुनाव में जितने पैसे खर्च करने को कहा जाता हैं उम्मीदवार उसके इतर कहीं ज्यादा धन खर्च करते हैं। उनका यह धन उनकी सहयोगी पार्टियां वाहन करती हैं। उनको सिर्फ जीत का टारगेट दिया जाता है जिसकी पटकथा खुद लिखती हैं। डूसू चुनाव फिलहाल संपन्न हो गए हैं लेकिन चुनाव से पूर्व करीब दो सप्ताह तक भारी शोर देखने को मिला। तकरीबन सभी कालेज पोस्टरों से पट जाते हैं। खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बड़े चुनावों की तरह सभी प्रत्याशी छात्रों को बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं। इस बार डीयू में भाजपा समर्पित विंग एबीवीपी चुनाव मैदान में उनको जीताने के लिए भाजपा की ओर से करीब दर्जन भर प्रवक्ताओं, केंद्र के कुछ मंत्री, स्थानीय नेताओं व सैकड़ों कार्यकताओं को लगाया गया था। दरअसल आम चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव उनमें देश के युवाओं को जोड़ने का काम एबीवीपी करती है। इसलिए एबीवीपी का जीतना भाजपा के लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए भाजपा की नेशनल लीडरशिप की नजरें परिणाम पर टिकी होती हैं। जब रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो सभी ने राहत की सासें लीं।

भाजपा के लिए एबीवीपी का जीतना इसलिए भी जरूरी था। क्योंकि उनकी जीत के सहारे ही भाजपा फिर से दिल्ली में वापसी की पटकथा लिखना चाहती थी। खैर, अब एबीवीपी ने जीत हासिल कर भाजपा की केंद्रीय लीडिरशिप को खुश कर दिया है। वहीं एबीवीपी की तरह कांग्रेस के लिए एनएसयूआई छात्र संगठन अपनी जिम्मेवारी निभाता है। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस की जीत में एनएसयूआई का बड़ा रोल रहा था, जिसमें एबीवीपी फिस्स हो गई थी। डीयू चुनाव में इस बार एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था। पर आम आदमी पार्टी की यूथ विंग सीवाईएसएस और वामपंथी आईसा गठबंधन के चुनाव में कूदने से मुकाबला त्रिकोणीय भी माना जा रहा था। सीवाईएसएस व आईसा की तरफ से अध्यक्ष पद पर आईसा के अभिज्ञान ताल ठोक रहे थे। उपाध्यक्ष पद पर आईसा की उम्मीदवार अंशिका सिंह मैदान में थीं। सीवाईएसएस के चंद्रमणि देव और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर सन्नी तंवर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन सभी औंधें मुंह गिर गए। उनकी हार की मुख्य वजह भी सामने है। मौजूदा समय की बात करें तो दिल्ली में आप पार्टी और वामपंथी दलों की हालात ज्यादा ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता ने पहले ही अरविंद केजरीवाल को नकार रखा है। अब उनकी हवाहवाई बातों से जनता किनारा कर चुकी है। इसलिए मुकाबला भाजपा व कांग्रेस छात्र विंग के बीच ही माना जा रहा था और हुआ भी वैसा ही।

इससे पहले भी एबीवीपी ने 2014 और 2015 में एनएसयूआई, सीवाईएसएस (आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई) और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (आईसा) को हराकर डूसू के सभी चारों पदों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार सूफड़ा साफ करने में एबीवीपी नाकाम रही। एक सीट उनको गवानी पड़ी जो एनएसयूआई के खाते में गई। लेकिन वोट प्रतिशत में इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले इजाफा हुआ। देश में हाल ही में कई जगहों पर छात्रसंघ चुनावों में एबीवीपी ने जीत प्राप्त की है। उनकी जीत ने भाजपा और तमाम हिन्दू संगठनों को खुश तो जरूर कर दिया है। लेकिन अब स्थिति पहले से बदली हुई है। कच्चे तेलों पर महंगाई ने जिस तरह से आग लगा रही है उससे देश के युवा केंद्र सरकार से खासे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। यही वजह है दो दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय चुनाव परिणामों में भी युवाओं ने सभी दलों के समर्पित छात्र संगठनों को धूल चटा दी। सभी पदों पर निर्दलीयों ने जीत हासिल कर सियासी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया।

अब एक सवाल यह उठ रहा है क्या साढ़े चार साल पुरानी मोदी सरकार के कामकाज से छात्र नाखुश हैं। क्या कॉलेजों में भगवा और सुधार के एजेंडे को लागू करने की कसरत के खिलाफ माहौल है या फिर भाजपा और उनके सहयोगी संगठनों के सपने बड़े हैं और इस हिसाब से तैयारी छोटी है? इसकी समीक्षा लोग अपने स्तर पर जरूर कर रहे हैं लेकिन डीयू चुनाव रिजल्ट जब एबीवीपी के पक्ष में आया तो यह तय हो गया कि देश का युवा अब भी भाजपानीत सरकार और मोदी की नीति में विश्वास कर रहा है। डूसू में एबीवीपी की शानदार जीत परिषद के भीतर आत्मविश्वास को भरने और भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ाने का काम करेगा। कुछ ही महीनों बाद देश में आम चुनाव होने हैं जिनमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। एबीवीपी भाजपा के लिए युवाओं को जोड़ने का काम करती है। इस बार भी उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय में जीत के बाद भाजपा ने जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की, उससे संकेत मिल जाते हैं कि वह युवाओं के भरोसे एक बार फिर केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की योजना बना रही है। अगर दिल्ली के चुनाव को युवाओं का नजरिया माना जाए, तो कांग्रेस की राह बड़ी मुश्किलों भरी हो सकती है।

रमेश ठाकुर
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

सरकार की नजर में कई ऐसी दवाएं हैं, जिन्हें खुले बाजार में बेचने से रोका जा सकता है। सरकार ऐसी किसी दवा को मंजूरी नहीं देगी, जो घातक है।

अश्विनी कुमार चौबे, स्वास्थ्य राज्यमंत्री

सरकार ने 328 दवाओं पर रोक लगाकर बेहतर काम किया है, पर अब तक जो लोग इन दवाओं को खा रहे थे, उनकी सेहत का क्या? सरकार अब गंभीरता से काम करे।

अभिषेक सिंघवी, कांग्रेस नेता

सत्यार्थ

माता का विश्वास

थॉमस अल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक मुड़ा हुआ कागज दिया और कहा कि यह ले जाकर अपनी मां को दे देना। वे उसे घर ले आए और अपनी मां को वह कागज देते हुए कहा- टीचर ने यह आपको देने को कहा है। मां ने वह कागज हाथ में लिया और पढ़ने लगीं। पढ़ते-पढ़ते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एडिसन ने मां से पूछा- इसमें क्या लिखा है मां, यह पढ़कर तुम रो क्यों रही हो। आंसू पोंछते हुए मां ने कहा- इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत

होशियार है और हमारा स्कूल नीचे स्तर का है। यहां अध्यापक भी बहुत शिक्षित नहीं हैं। इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं शिक्षा दें। उस दिन के बाद से मां खुद उन्हें पढ़ाने लगीं और मां के ही मार्गदर्शन में एडिसन पढ़ते रहे, सीखते रहे। कई वर्षों बाद मां गुजर गईं। मगर तब तक एडिसन प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे और उन्होंने फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। एक दिन फुरसत के क्षणों में वे अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे। तभी उन्होंने आलमारी के एक कोने में एक पुराना पत्र देखा व उत्सुकतावश उसे खोलकर पढ़ने लगे। यह वही पत्र था, जो छोटे में एडिसन के शिक्षक ने उन्हें दिया था। उन्हें याद आया कि कैसे स्कूल में उन्हें होशियार घोषित कर दिया गया था। मगर पत्र पढ़कर वे अचंभे में पड़ गए। उस पत्र में लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है। इसलिए उसे अब स्कूल न भेजें। अचानक एडिसन की आंखों में से आंसू झरने लगे। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माता ने बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया।

जयति गोयल

505 अंक की भारी गिरावट लेकर बंद हुआ सेंसेक्स

मुंबई। जब सुबह शेयर बाजार खुला तो उसमें गिरावट देखने को मिली, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की और कारोबार की समाप्ति पर भी घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। गिरावट के इस माहौल में कारोबार की समाप्ति पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का तीस शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 505.13 अंक यानि 1.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 37,585.51 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पचास शेयरों वाले निफ्टी पर भी कारोबार की समाप्ति पर गिरावट हावी रही और ये लाल निशान पर पहुंचकर 137.45 अंक यानि 1.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 11,377.75 के स्तर पर बंद हुआ।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ हरे निशान पर हुई और कारोबार की समाप्ति पर घरेलू शेयर बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ । काराबोर की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का तीस शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 247.85 अंक यानि 0.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 37,965.81 के स्तर पर खुला और काराबोर की समाप्ति पर ये 372.68 अंक यानि 0.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 38,090.64 के स्तर पर बंद हुआ ।

वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का पचास शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी भी काराबोर की शुरुआत में 88.90 अंक यानि 0.78 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,458.80 के स्तर पर खुला और काराबोर की समाप्ति पर ये 145.30 अंक यानि 1.28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,515.20 के स्तर पर बंद हुआ ।

बिजली का भाव हाजिर बाजार में 14.08 रुपये प्रति यूनिट पर

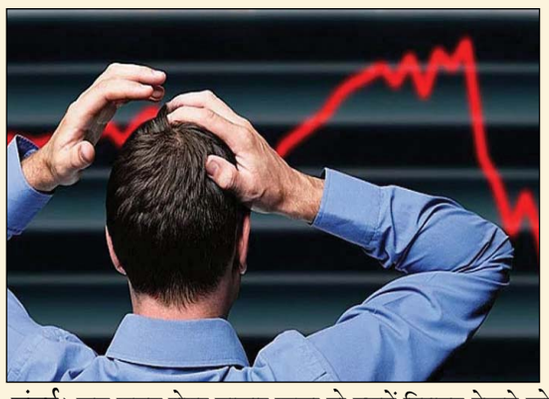

नयी दिल्ली। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में सोमवार को एक दिन पहले के हाजिर (डीएमए) सौदों में बिजली का भाव 14.08 रुपये प्रति यूनिट पर पहुंच गया जो इस बाजार का मूल्य पांच साल का उच्चतम स्तर है। आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ने के कारण हाजिर बाजारमें बिजली की दरें बढ़ी हैं। एक सूत्र ने कहा, ‘‘ मंगलवार की आपूर्ति के लिए बिजली का हाजिर बाजार मूल्य पांच साल के उच्च स्तर 14.08 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गया।’’ उसने कहा, ‘‘इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में सोमवार को डीएएम कारोबार के दौरान बिजली के दाम में वृद्धि का प्रमुख कारण मांग में बढ़ोतरी तथा कम आपूर्ति है। बाजार में मांग 26.5 करोड़ यूनिट की थी जबकि पेशकश 20 करोड़ यूनिट आयी।’’ सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘मांग में वृद्धि का कारण बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी के साथ पवन और पनबिजली उत्पादन में कमी है।’’उसने कहा कि स्वतंत्र तथा निजी उपयोग वाले बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी के कारण निजी इस्तेमाल को लेकर बिजली की मांग बढ़ी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में रविवार को सोमवार को होने वाली आपूर्ति के लिये हाजिर बिजली मूल्य 12.95 रुपये प्रति यूनिट पर पहुंच गया। जहां मांग 29.8 करोड़ यूनिट थी वहीं आपूर्ति 19.2 करोड़ यूनिट थी। इससे पहले, इस वर्ष मई में बिजली का हाजिर बाजार मूल्य पांच साल के उच्चतम स्तर 11.41 रुपये यूनिट पर पहुंचा था।

पतंजलि के सस्ते दूध के बावजूद मदर डेयरी नहीं घटाएगी दाम

नयी दिल्ली। दूध, दही और सब्जी जैसे उत्पाद बेचने वाली मदर डेयरी ने कहा है कि वह किसी अन्य इकाई से प्रतिस्पर्धा के लिये कंपनी अपने गाय के दूध के दाम काम नहीं करेगी। मदर डेयरी ने यह बात पतजंलि समूह के कम दर पर गाय-दूध के साथ बाजार में उतरने की घोषणा के बाद कही है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी और दिल्ली के आसपास प्रतिदिन करीब 7 लाख लीटर गाय का दूध बेचने वाली मदर डेयरी ने यह भी भरोसा जताया कि इस खंड में और कंपनियों के आने से उसकी बिक्री मात्रा प्रभावित नहीं होगी। हरिद्वार की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने 40 रुपये लीटर के भाव पर गाय का दूध बाजार में बेचने की घोषणा की है। वहीं मदर डेयरी इसके लिये 42 रुपये लेती है। मदर डेयरी फ्रुट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लि. के निदेशक सौगत मित्रा ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘हम प्रतिस्पर्धा का स्वागत करते हैं। पतंजलि समूह के प्रवेश से गाय दूध खंड में बाजार का आकार बढ़ेगा।

इससे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी दाम कम करेगी, उन्होंने कहा, ‘‘हम न तो गाय के दूध का दाम बढ़ाएंगे और न ही उसमें कमी लाएंगे।’’पिछले सप्ताह बाबा रामदेव की पंतजलि आयुर्वेद ने गाय का दूध और दूध के उत्पाद पेश कर इस खंड में दस्तक दी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 तक करीब 1,000 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य रखा है। अमूल और पराग मिल्क ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गाय का दूध पेश किये हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। हमारे ग्राहक ब्रांड को लेकर निष्ठावान है।’’ मित्रा ने कहा, ‘‘डिब्बाबंद गाय के दूध का बाजार 10-12 लाख टन प्रतिदिन है। हम फिलहाल करीब 7 लाख लीटर प्रतिदिन बेचते हैं और अगले साल मार्च तक 8 लाख लीटर पहुंच जाने का अनुमान है।’’ उन्होंने कहा कि नई कंपनियों के आने से बाजार का आकार बढ़ेगा। कुल मिलाकर मदर डेयरी करीब 36 से 37 लाख लीटर दूध प्रतिदिन आपूर्ति करती है। इसमें से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 32 लाख लीटर 1,400 खुदरा दुकानों के जरिये बेचे जा रहे हैं।

विजया बैंक, देना बैंक, बैंक आफ बड़ौदा का होगा विलय : सरकार

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

सरकार ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों-बैंक आफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का आपस में विलय किया जाएगा। इसके साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक अस्तित्व में आएगा।यह निर्णय बैंकों की कर्ज देने की ताकत उबारने और आर्थिक वृद्धियों को गति देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी पांच अनुषंगी इकाइयों का स्वयं में विलय किया था। साथ ही महिलाओं के लिये गठित भारतीय महिला बैंक को भी मिलाया था। योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे बैंक मजबूत और मजबूत होंगे तथा उनकी कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी।

विलय के कारणों को बताते हुए उन्होंने कहा बैंकों की कर्ज देने की स्थिति कमजोर होने से कंपनियों का निवेश प्रभावित हो रहा है।वित्त मंत्री ने कहा कि कई बैंक नाजुक स्थिति में है और इसका कारण अत्यधिक कर्ज तथा फंसे कर्ज (एनपीए) में वृद्धि है। उन्होंने कहा, ‘‘विलय के बाद अस्तित्व में आनी वाली इकाई बैंक गतिविधियां बढ़ाएंगी।’’।एसबीआई की तरह विलय से तीनों बैंकों के कर्मचारियों की मौजूदा सेवा शर्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की 21 बैंकों में बहुलांश हिस्सेदारी है। इन बैंकों की एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बैंक परिसपंत्ति में दो तिहाई से अधिक हिस्सेदारी है।

हालांकि इसके साथ इन सार्वजनिक बैंकों का फंसे कर्ज में भी बड़ी हिस्सेदारी है। इस डूबे कर्ज के कारण क्षेत्र प्रभावित है और वैश्विक बासेल-तीन पूंजी नियमों के अनुपालन के लिये अगले दो साल में करोड़ों रुपये चाहिए। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तीनों बैंकों के निदेशक मंडल विलय प्रस्ताव पर विचार करेंगे। ‘इस विलय से परिचालन दक्षता और ग्राहकों की मिलने वाली सेवा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि विलय के बाद अस्तितव में आने वाला बैंक तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा पैमाने की मितव्ययिता के साथ मजबूत प्रतिस्पर्धी होगा।

कुमार ने कहा कि नेटवर्क, कम-लागत जमा और अनुषंगी इकाइयों के मामले में बेहतर तालमेल होगा। ।उन्होंने कहा कि कर्मचारियो के हितों तथा ब्रांड इक्विटी का संरक्षण किया जाएगा।कुमार ने कहा कि देना बैंक, विजया बैंक और बैंक आफ बड़ौदा के पूंजी समर्थन सुनिश्चित किया जाएगा।तीनों बैंक विलय के बाद स्वतंत्र रूप से काम करते रहेंगे।

संशोधित जनधन योजना में 20 लाख लोग शामिल, खाताधारकों की संख्या 32.61 करोड़ पहुंची

नई दिल्ली (एजेंसी)।

संशोधित प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) में पांच सितंबर तक कम-से-कम 20 लाख लोग शामिल हुए हैं। इसके साथ वित्तीय समावेश के इस प्रमुख कार्यक्रम में खाताधारकों की कुल संख्या बढ़कर 32.61 करोड़ हो गई है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने पीएमजेडीवाई को उच्च बीमा कवच के साथ खुली अवधि वाली योजना के रूप में दोबारा शुरू कर दिया और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा को दोगुना कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अगस्त को समाप्त हुई चार साल की अवधि से आगे इस योजना को जारी रखने का फैसला किया जिसका उद्देश्य औपचारिक बैंकिग प्रणाली को ''हर घर से हर वयस्क’’ तक ले जाना है।

माइक्रोमैक्स और जियो को छत्तीसगढ़ सरकार से मिला 1,500 करोड़ रुपए का ठेका

वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 15 अगस्त से 5 सितंबर की अवधि के दौरान, 32.61 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि में 1,266.43 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी गई। पीएमजेडीवाई खातों में पांच सितंबर को शेष धन 82,490.98 करोड़ रुपए था। संशोधित योजना के तहत, 28 अगस्त के बाद नए पीएमजेडीवाई खातों के तहत नए रुपे कार्डधारकों के लिए आकस्मिक बीमा कवर एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, 5,000 रुपए की मौजूदा %ओवर ड्राफ्ट’ (ओडी) सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, 2,000 रुपए तक के ओडी के लिए कोई शर्त नहीं जुड़ी होगी।

आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 28 अगस्त के बाद पीएमजेडीवाई खाते खोलने वाले करीब 7.18 लाख लोग 2 लाख रुपए के आकस्मिक बीमा कवर का लाभ उठा सकते हैं। अगस्त 2014 में शुरू पीएमजेडीवाई के पहले चरण में बुनियादी बैंक खातों और रुपे डेबिट कार्ड खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसमें 1 लाख रुपए के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर शामिल था। इसके अलावा, यह छह महीने के बाद 5000 रुपए की ओडी सुविधा के साथ बुनियादी बैंकिंग खाते की सुविधा प्रदान करता है। पीएमजेडीवाई खाताधारकों का लगभग 53 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि कुल खातों में से 83 प्रतिशत आधार से जुड़े हैं।

पेट्रोल की ऊंची कीमतों का असर त्योहार पूर्व खरीदारी पर : सर्वेक्षण

नयी दिल्ली। त्योहारी मौसम से ठीक पहले पेट्रोल के बढ़े दाम उपभोक्ताओं को परेशान कर रहे हैं और उन्हें इसकी भरपाई के लिए घरेलू खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। एक सर्वेक्षण में यह बात कही गयी है। लोकलसर्किल्स ने अपने हालिया सर्वेक्षण में कहा, ‘‘त्योहारी मौसम नजदीक आ रहा है। हर कोई उपहारों पर खर्च करना चाह रहा है। लोग लंबे समय से घर के उपकरणों को बदलना चाह रहे हैं। हालांकि पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतें त्योहार पूर्व उत्साह को फीका कर रही हैं।’’उसने कहा, ‘‘यह मध्यम श्रेणी के भारतीयों पर भारी बोझ है और उनमें से अधिकांश इससे कराह रहे हैं तथा इसकी भरपाई घरेलू खर्च में कमी लाकर कर रहे हैं।’’78 प्रतिशत लोग बाहर खाने जाना, यात्रा करना, सिनेमा देखना, खरीदारी करना आदि में कमी ला चुके हैं या ऐसा करने की उनकी योजना है।

खादी इंडिया ने प्लास्टिक कचरे से बना इको-फ्रेंडली बैग लांच किया

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान में एक अलग ढंग से अपना योगदान देते हुये ‘खादी इंडिया’ ने प्लास्टिक कचरे और कागज की लुगदी के मिश्रण से बना एक डिजाइनर बैग लांच किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने शनिवार को स्वच्छता दिवस के अवसर पर यहां कनॉट प्लेस स्थित अपने प्रमुख स्टोर में प्लास्टिक-पेपर मिश्रित व पर्यावरण के अनुकूल हस्तनिर्मित बैग की प्रदर्शनी लगाई। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरूआत की, इस मौके पर खादी इंडिया ने देशभर के अपने सभी स्टोर पर सामान ले जाने वाले बैग को पेश किया है। सक्सेना ने बताया कि केवीआईसी ने इस अनूठे बैग को बनाने के लिए जयपुर स्थित कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित पेपर संस्थान (केएनएचपीआई) में यह प्रयोग किया। सक्सेना ने बताया, ‘‘केएनएचपीआई के अधिकारियों को प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर फिर उसकी आवश्यक सफाई और प्रसंस्करण के बाद उसमें 20 प्रतिशत तक कागज की लुगदी मिलाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें यह देखना था कि प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल हस्तनिर्मित पेपर उद्योग में किया जा सकता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग सफल रहा।

महंगा हो सकता है सोना, सरकार बढ़ा सकती है 3 फीसद आयात शुल्क

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सरकार सोने पर आयात शुल्क 3 फीसद बढ़ा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में गोल्ड के भाव में बढ़ोत्तरी की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राजकोषीय घाटे को काबू में करने के लिए सरकार ऐसे कदम उठा सकती है। फिलहाल सोने पर 10 फीसद की इंपोर्ट ड्यूटी है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार सोने में सीधे निवेश के बजाय सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड जैसी स्कीम को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। वहीं बुलियन डीलर्स के मुताबिक चुनाव और फेस्टिवल सीजन में सोने की मांग को देखते हुए सरकार ऐसा नहीं करेगी। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (ढ्ढक्चछ्व) के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि मौजूदा स्थिति में इंपोर्ट ड्यूटी को 2 फीसद बढ़ाना सही रहेगा।

वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री के कुछ जानकारों का मानना है कि सोने की मांग पर रोक के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियम लागू होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सोने के अंतरराष्ट्रीय भाव और भारत के भाव में 8 से 10 फीसद का अंतर है। अगर यह और ज्यादा बढ़ता है तो सोने की तस्करी बढ़ जाएगी। जाहिर है ड्यूटी बढ़ने से सोने के भाव में वृद्धि होगी। ऐसे में मान लिया जाए कि अगर ड्यूटी में 2 फीसद की भी बढ़ोत्तरी होती है तो सीधे भाव में 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त आ जाएगी।

प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को पार कर लेने की उम्मीद : सीबीडीटी प्रमु

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य से अधिक रहने का भरोसा जताया। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 11.5 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह होने का बजट लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार ने प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 14.3 प्रतिशत बढ़कर 11.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है।

चंद्रा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.5 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक रहेगा।’’ हालांकि, महालेखा नियंत्रक के आंकड़े के अनुसार अप्रैल-जून अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह मामूली रूप से सालाना आधार पर 4.2 प्रतिशत बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो गया। चंद्रा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक कर रिफंड करीब 95,000 करोड़ रुपये रहा है। इस साल सरकार ने लंबित प्रत्यक्ष कर वापसी के लिये एक से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया।

वित्त मंत्रालय ने पूर्व में एक बयान में कहा था कि लंबित दावों में से 99 प्रतिशत से अधिक का निपटान किया गया है। पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18 प्रतिशत बढ़कर 10.03 लाख करोड़ रुपये रहा। चंद्रा ने कहा कि फ्लिपकार्ट-वालमार्ट सौदे में लगभग 7,500 करोड़ रुपये कर के रूप में सरकार को मिले हैं। वालमार्ट ने फ्लिपार्ट में 77 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण सौदा पूरा कर लिया है। कंपनी ने इसके लिये 16 अरब डालर का भुगतान किया है।

सौदे के तहत कंपनी ने भारतीय कानून के तहत फ्लिपकार्ट के शेयरधारकों को भुगतान करते समय विदहोल्डिंग कर काटा है। विदहोल्डिंग कर एक प्रकार का आयकर है जो कि भुगतान करने वाले को सरकार को देना होता है। इसमें आय प्राप्त करने वाले के बजाय इसका भुगतान करने वाला कर काट कर सरकार को चुकाता है।

घरेलू कर कानून के तहत विदेशी निवेशकों द्वारा खरीदने के 24 महीने बाद बेचे जाने वाले शेयरों पर 20 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है। हालांकि, आयकर कानून में कम दर पर अथवा शून्य दर पर भी कर देने का प्रावधान है बशर्ते कि उस देश के साथ जहां से निवेश किया गया है भारत का दोहरे कराधान से बचने का समझौता हुआ हो।

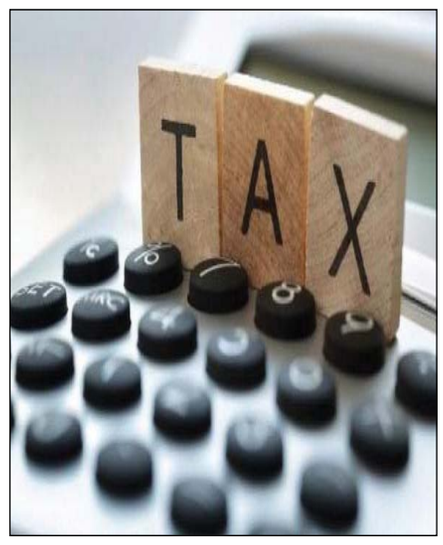

सूरत। सचीन पलसाना रोड पर अनमोल नगर में मिला जहरीला कोमिकल जो सूरत के बाहर से लाकर यहा पर खाली करने का अवैध धंधा काफी समय से चल रहा है। जिसके बाद आये दिन इस तरह की घटनाक्रम सामने आते रहते है।

सूरत। लाजपोर सचिन में गौरी गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते भक्त।

आाकाश होटल से जुआ खेलते पांच गिरफ्तार

सूरत। शहर के लाल दरवाजा में स्थित आकाश होटल में पुलिस ने छापा मारकर जुआ खेल रहे पांच लोगों को नगद 11800 रूपए के साथ गिरफ्तार किया। महीधरपुरा पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर गत रोज शाम में लाल दरवाजा में स्थित आकाश होटल में छापेमारी की गई थी। जिसमें रूम नं.301 में से जुआ खेलते जस्मीन कोटडिया, भरत जयचंद शाह, रीतेश जोषी, विनोद शाह और मुकेश जासोलिया गिरफ्तार हुए। पुलिस ने जुआरियों के पास से नगद 11800 रूपए बरामद किया। जस्मीन कोटडिया होटल में किराए से रूम बुक कराकर अपने आर्थिक लाभ के लिए बाहर से लोगों जुगा खिलाने के लिए बुलाता था।

गणपति बप्पा मोरिया.....

उधना रेल्वे स्टेशन आर.पी.एफ उधना

धागीना नगर उधना

विनय नगर सोसायटी उधना।

विघ्नहर्ता मित्र मंडल, जीगन नगर नवागाम।

कांग्रेस आज गुजरात विधानसभा की घेराबंदी करेगी

अहमदाबाद। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर गुजरात सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कल से गुजरात विधानसभा का दो दिवसीय सत्र प्रारंभ हो रहा है और प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा घेरने का आयोजन किया है। किसानों के साथ कांग्रेस पहले किसान आक्रोश रैली निकालेगी और बाद में विधानसभा की घेराबंदी करेगी। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक वह इस लड़ाई को जारी रखेगी।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार परिषद में प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धानाणी ने भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीति नियम किसान विरोधी हैं। सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन कांग्रेस किसानों के दर्द और समस्याओं की आवाज बनेगी और सरकार के खिलाफ किसानों का कर्ज माफ करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करेगी। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर देती। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया तो भाजपा को जड़ से खत्म करने के संकल्प के साथ गुजरात प्रदेश कांग्रेस विधानसभा की घेराबंदी करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई उद्योपतियों के पोषण के सरकार 43 वस्तुओं पर वेट वसूली करती है। आंकड़ों में छेड़छाड़ कर सच्चाई जनता से छिपाई जा रही है।

बजट सत्र के बाद 18 सितंबर से विधानसभा के दो दिवसीय संक्षिप्त सत्र हो रहा है और इस सत्र के दौरान सदन में विपक्ष ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। खासकर किसान, पानी, बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के मुद्दे पर सरकार जबर्दस्त दबाव बनाने की कांग्रेस की रणनीति है। दूसरी ओर गांधीनगर की सत्याग्रह छावनी में किसान आक्रोश रैली का कांग्रेस ने आयोजन किया है। जिसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ विधानसभा की घेराबंदी करेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ से सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। वहीं विधानसभा में कांग्रेस के उप नेता शैलेष परमार ने सरकार के खिलाफ अविश्वास की दरखास्त की है।

गर्भवती महिला को जिंदा जलाने का प्रयास, हालत गंभीर

राजकोट। जिले के कांधवालिया गांव में रसोई में देर होने पर सास द्वारा गर्भवती बहु को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। गंभीर रूप से झुलसी गर्भवती महिला को पहले जसदण और बाद में राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है।

जानकारी के मुताबिक राजकोट जिले की वींछिया तहसील के कांधेवाली गांव में लता गोविंदभाई गोरावा नामक महिला को रसोई बनाने में देर हो गई। जिसे लेकर उसकी सास जमना गोरावा गुस्से में भड़क उठी और लता पर केरोसिन छिड़कर उसे आग के हवाले कर दिया। लता गर्भवती थी, परंतु जमना गोरावा को उस पर तरस नहीं आया। इस घटना में लता गोरावा 75 फीसदी से झुलस गई। गंभीर हालत में लता को पहले जसदण के अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में राजकोट के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के मुताबिक लता को डेढ महीने का गर्भ और उस पर फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। लता की तबियत में सुधार होने के बाद उसके गर्भ की रिपोर्ट करवाई जाएगी। वींछिया पुलिस ने लता की सास जमना गोरावा के खिलाफ दफा 307 के तहत हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की दिशा में कार्यवाही तेज की है।

कार-स्कूल बस के बीच दुर्घटना में कार चालक की मौत

सूरत। सूरत के कडोदरा के निकट नेशनल हाईवे पर कार और स्कूल बस के बीच हुई दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई। जबकि स्कूल बस पलटी खा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की।

जानकारी के अनुसार सूरत की जीनियस एकेडेमी स्कूल की बस का ड्राइवर विद्यार्थियों को लेने जा रहे थे। उस वक्त मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार स्कूल से तेज धमाके के साथ टकरा गई। इस हादसे में स्कूल बस पलट गई। घटना के दौरान बस में विद्यार्थियों के नहीं होने से बड़ी जानहानि टल गई। जबकि दुर्घटनाग्रस्त कार में चालक समेत दो लोग बुरी तरह फंस गए। सूचना मिलते ही एम्ब्युलैंस 108 समेत पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। हांलाकि तब तक कार चालक बंसीलाल बिस्नोई की मौत हो चुकी थी। कार में सवार दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से बड़ी मात्रा में शराब बरामद कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी।

अहमदाबाद शहर के गुरुकुल रोड पर एक मॉल के सामने गोदाम में आग लगने पर सनसनी मच गई। आग के कारण निकट के फ्लेट में रहते लोगों को फायर की मदद से बाहर निकाला गया।

हिट एन्ड रन की घटना में रिलायन्स के सिक्युरिटी गार्ड की मौत

सूरत। सूरत के हजीरा क्षेत्र में हिट एन्ड रन की घटना में रिलायन्स के सिक्युरिटी गार्ड की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब गार्ड सड़क पार कर रहा था और तेज रफ्तार बाइक ने उसे उड़ा दिया।

जानकारी के मुताबिक सूरत के हजीरा स्थित रिलायन्स कंपनी का सिक्युरिटी गार्ड कंपनी की ओर रहा था। उस वक्त कंपनी के गेट संख्या 4 के निकट गार्ड सड़क पार कर रहा था, तब एक तेज रफ्तार मोटर साइकिल सवार ने उसे उड़ा दिया। हादसे के बाद बाइक सवार घटनास्थल से फरार हो गया। कंपनी के कर्मचारियों ने गंभीर रूप से घायल गार्ड को फौरन निजी अस्पताल पहुंचाया। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पूरी घटना निकट लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फूटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू की है।

सूरत। पेड गिरने से दो चार चक्का गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। यह घटना वराछा खोडियार नगर में चंद किरण अपार्टमेंट के पास की घटना है। इस घटना में किसी प्रकार की जन नहीं हुई है।

महादेव मीडिया

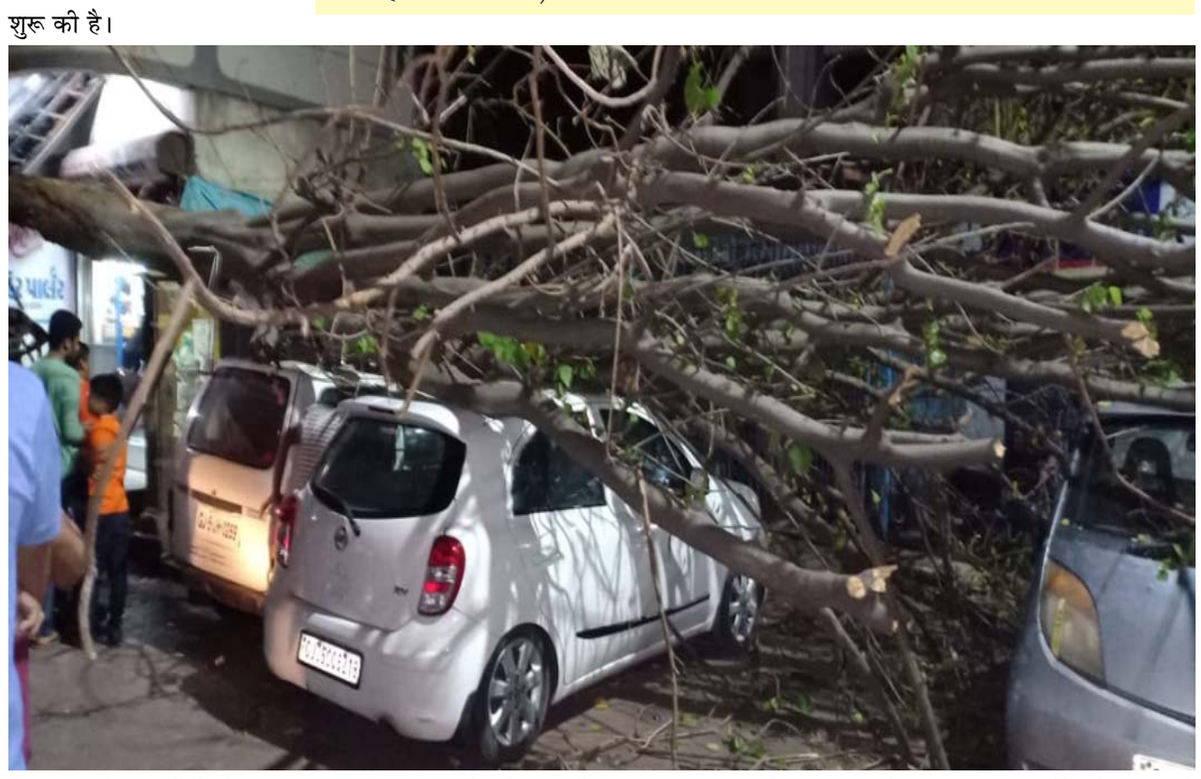

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com